

Volume 02 Issue 11 27<sup>th</sup> November 2017





at the International Rice Research Institute
Los Baños, Philippines

# Moody's upgrades India's rating, changes outlook to stable from positive

In a remarkable feat, Moody's Investors Services upgraded the ratings of Sovereign Credit to Baa2 from Baa3 for the first time since 2004. This increase in ratings can be accredited to the structural and institutional reforms by the Modi Government including GST, Demonetisation, Aadhaar, DBT etc. These reforms will translate into an improved business climate, formalize the economy, and increase lending among other benefits such as reduction in corruption and debt. Moody's outlook for sovereign rating also changed from 'positive' to 'stable'.

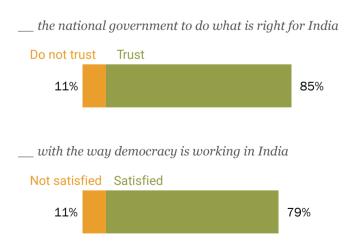


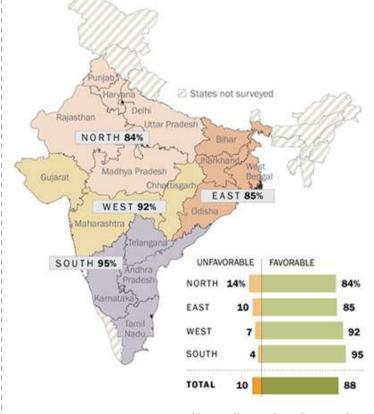
# Indians happy with state of economy, working of Democracy and Government under Narendra Modi

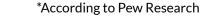
Citizen empowerment has always been the focal point of the Narendra Modi Government. From bold and decisive moves like Demonetization and GST to diplomatic victories and increased international cooperation, India has seen a remarkable growth in the last three years. Echoing the sentiments of the Indian citizen, the study by American think tank Pew Research Centre shows that the majority are happy with the current state of the economy and the direction of the country.

Nearly nine-in-ten Indians hold a favorable opinion of PM Modi who is very popular among men and women and among adults in both rural and urban area, especially youngsters. Furthermore, the share of adults who feel that the economy is "very good" has tripled in the past three years.

## Indians very satisfied with their government and their democracy













## मूडीज़ ने बढ़ाई भारत की रेटिंग, सकारात्मक से स्थिर श्रेणी में हुआ रेटिंग का आउटलुक

मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस (मूडीज़) ने भारत की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता की रेटिंग में सुधार किया है। 2004 के बाद पहली बार क्रेडिट रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर Baa2 कर दिया गया है। क्रेडिट रेटिंग में यह सुधार मोदी सरकार के जीएसटी, विमुद्रीकरण, आधार और डीबीटी समेत कई संरचनात्मक और संस्थानात्मक सुधारों की वजह से हुआ है। इन सुधारों की वजह से न केवल व्यापार के अनुकूल माहौल बना और अर्थव्यवस्था संगठित हुई बल्कि भ्रष्टाचार और ऋण दर में भी कमी आई है। साथ ही मूडीज ने रेटिंग के आउटलुक को बदल कर सकारात्मक से स्थिर श्रेणी में कर दिया है।



### देश की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र की स्थिति और नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से संतृष्ट हैं भारतीय

नागरिकों का सशक्तिकरण हमेशा से नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथिमकताओं में रहा है। विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे साहसी और निर्णायक फैसले से लेकर कूटनीतिक जीत तक, पिछले तीन सालों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल किया है। अमेरिकन थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन से केंद्र सरकार के संबंध में भारत की जनता के मत का पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश भारतीय देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थित और देश की दिशा से संतुष्ट हैं।

लगभग दस में से नौ भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है और वे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के वयस्क महिला एवं पुरुषों में, खासकर युवाओं में, बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को 'बहुत अच्छी' बताने वाले वयस्कों

के आंकड़े में पिछले तीन साल में तीन गुनी वृद्धि हुई है

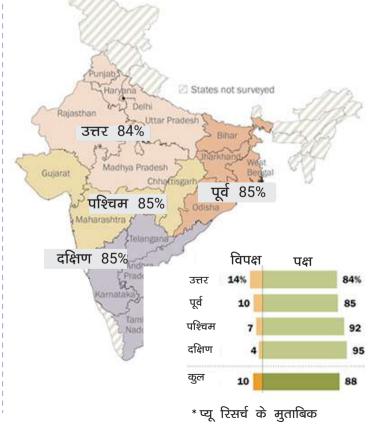
#### देश की सरकार हमेशा राष्ट्रहित में कार्य करती है

\_ देश की सरकार हमेशा राष्ट्रहित में कार्य करती है



\_ देश में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर राय











### Philippines honours PM Modi: Rice Field Laboratory named after him

PM Narendra Modi visited Philippines during the ASEAN summit and addressed the Indian community present there. The Prime Minister spoke about India's strong bonding with ASEAN as well as the shared heritage. He said the Indian diaspora plays an important role in maintaining and nurturing this shared heritage. He encouraged the Indian community and shared that everyone together should work in their capacity to ensure that the 21st century which is termed as Asia's century becomes 'India's century' too.

During the Prime Minister's visit to Manila, he also visited the International Rice Research Institute (IRRI) and met a large number of Indian scientists working there. He donated two Indian seed varieties to the bank and also inaugurated a 'rice field laboratory' named in his honour.

#### Prime Minister Narendra Modi attends 15th ASEAN-India Summit

Prime Minister Narendra Modi visited Manila on the occasion of the 15th ASEAN-India Summit. This was the 50th year of ASEAN's establishment and the Prime Minister spoke on ASEAN's journey of transformation. During his address, the Prime Minister spoke about ASEAN's commitment to focus on one vision, one identity as an independent community. He further said India's Act East Policy is based on ASEAN with a focus on regional security of the Indo-Pacific region. With regard to the 3rd ASEAN-India Plan of Action, the Prime Minister noted the progress and said that the three crucial pillars of politico-security, economic and cultural partnership have been covered. The Prime Minister also said that the 1.25 billion people of India are keen to welcoming ASEAN leader on India's 69th Republic Day Celebrations.









### फिलीपींस में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान: उनके नाम पर राइस फील्ड लैबेरेटरी का नाम रखा गया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीपींस का दौरा किया और वहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत के आसियान क्षेत्र के साथ लंबे समय से साझा विरासत और भावनात्मक संबंध के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में साझी विरासत को आगे बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की विशेष भूमिका है। उन्होंने भारतीय समुदाय को प्रोत्साहित किया और कहा कि सभी एकजुट हो पूरी क्षमता से कार्य करें ताकि एशिया की शताब्दी कहे जाने वाले 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाया जा सके।

मनीला की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आईआरआरआई) का भी दौरा किया और वहाँ कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की। उन्होंने बैंक में बीज के दो भारतीय किस्मों का दान भी किया और साथ ही उन्होंने अपने सम्मान में नामित 'राइस फील्ड लेबोरेटरी' का उद्घाटन किया।

## 15 वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी

1 5वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला के दौरे पर गए। आसियान की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आसियान के विकास और इसके योगदानों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की एक दृष्टि, एक पहचान और एक स्वतंत्र समुदाय के रूप में काम करते रहने की प्रतिबद्धता के प्रति विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा के महत्व पर आधारित है। तीसरी आसियान-भारत कार्य योजना की प्रगति को बेहतरीन बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक सुरक्षाए आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदारी इस प्रगति के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 125 करोड़ भारतवासी अपने देश के 69 वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आसियान देशों के नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।







Moment of glory: India wins International Court of Justice seat

India's strong standing in the global arena has received yet another boost in the form of a diplomatic victory in the re-election of Dalveer Bhandari to the International Court of Justice (ICJ). The U.K. chose to withdraw their nomination after it was evident that it would not win the contest in the General Assembly (GA).

This is the first time that one of the five permanent members of the UNSC lost out to an ordinary member participating in a race—a proud moment

for the country. The winning candidate required a majority in both the GA and the UNSC, but 11 rounds of voting until last week ended, with India winning in the GA and the U.K. winning in the UNSC. As U.K. announced its exit from the race in the 12th round, Justice Bhandari won 183 of the 193 votes in the GA and also secured all 15 votes in the UNSC. This took place after separate elections were held at the U.N. headquarters in New York.

#### National Anti-Profiteering Authority- an entity to ensure fair pricing

A day after GST rate cut on several items, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the establishment of a powerful national entity to ensure the benefits of tariff cuts are passed on to consumers. Affected consumers who feel they did not receive any benefit commensurate to reduction in prices may apply for relief to the Screening Committee in their particular State. National Anti-Profiteering Authority is a one step forward that will give an institutional mechanism and aims at reassuring Government's commitments in the implementation of GST in terms of lower prices of the goods and services.



### Northeast to soon get India's first Air Dispensary

In a move to provide access to medical care, Union Ministry of Development of Northeast is all set to start a helicopter based air dispensary in Northeast. As a part of initial funding, DoNER has contributed Rs 25 crore for the initiative. The envisaged plan will be based at two locations, Imphal and Shillong. In a move to provide better facilities to citizens in remote areas, the government is keen on starting the project as early as January 2018.





## प्रमुख समाचार



वैश्विक स्तर पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। भारत के जिस्ट्स दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फिर से जज के तौर पर चुन लिया गया है। ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपने प्रत्याशी के जीतने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए इस दौर के मतदान से पहले ब्रिटेन ने अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने का फैसला किया। ऐसा पहली बार हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक देश का उम्मीदवार संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सदस्य देश के उम्मीदवार से हार गया। यह पल भारत के लिए गौरव का क्षण था।

आईसीजे चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में बहुमत प्राप्त करने की जरूरत होती है। लेकिन पिछले हफ्ते मतदान के 11 वें राउंड तक भारत महासभा में और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जीत रहा था. लेकिन 12 वें राउंड में ब्रिटेन ने दौड़ से बाहर निकलने की घोषणा की। 12 वें राउंड में हुए मतदान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 वोट और महासभा के 193 में से 183 वोट भारत के जिस्टिस भंडारी को मिले। भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव पर ऐसा अभूतपूर्व समर्थन नहीं मिला है।

## राष्ट्रीय मुनाफारवारी विरोधी प्राधिकरण- उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने की इकाई

कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय मुनाफाओरी विरोधी प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ता तक पहुंच पाए। ऐसे प्रभावित उपभोक्ता जिन्हें वस्तुएं या सेवाएं खरीदने पर जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे अपने संबंधित राज्य में छानबीन समिति के समक्ष राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुनाफारोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की घटी हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।



## पूर्वोत्तर क्षेत्र को जल्द मिलेगी भारत की पहली एयर डिस्पेंसरी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एक हेलीकॉप्टर आधारित 'एयर डिस्पेंसरी' शुरू करने दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने इस पहल के लिए आरंभिक वित्त पोषण के एक हिस्से के रूप में 25 करोड़ रूपये का योगदान पहले ही कर दिया है। आरंभ में इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर को दो स्थलों-मणिपुर के इम्फाल और शिलांग के मेघालय में अवस्थित किया जाएगा। चूँकि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवा सुलभ नहीं हो पाती है, इसलिए मंत्रालय 2018 से इस पहल की शुरुआत करने को उत्सुक है।





#### India reaches new heights with the successful testing of BrahMos



On 22nd November, 2017, India successfully test-fired the BrahMos cruise missile. The supersonic missile was fired from the Sukhoi-30 MKI fighter aircraft. The precision-guided missile was tested in the Bay of Bengal against a sea-based target. This integration of the cruise missile with fighter jets will enable the Air Force to conduct surgical strikes in a range up to 300 km. This test was a significant one for the nation as it completes the cruise missile triad.

#### **World Toilet Day celebrated countrywide**



#### **Tweet**



I compliment all those individuals and organisations working towards building more toilets in various parts of India. Their invaluable contribution adds solid momentum to Swachh Bharat Mission.

Narendra Modi @narendramodi

As the country celebrated World Toilet Day on 19th November, promotion of behaviour change and toilet usage activities were undertaken by the States and districts as a part of the Swachh Bharat Mission. The event witnessed processions, discussions and saw participation from school children in large numbers to bring out the importance of toilet usage and its access. The celebrations ushered in energizing people's participation for an open defecation free India. On the momentous occasion, the PM reiterated his government's commitment towards improving sanitation facilities across the nation.

#### Progressing towards a Clean India



Number of ODF villages- 2,76, 393



Number of ODF cities- 1, 337



Number of toilets constructed-

5, 85, 04, 277







## ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सफल, भारत को मिली ऐतिहासिक सफलता



22 नवंबर, 2017 को भारत ने ब्रह्मोस क्रुज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई से ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल पहला सफल परीक्षण किया गया है। लक्ष्य पर सदीक मार करने वाली इस मिसाइल को बंगाल की खाडी में छोडा गया और यह अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। लड़ाकू विमानों को क्रूज मिसाइल से लैस किए जाने पर वायू सेना ३०० किमी की दूरी तक सर्जिकल हमले करने में सक्षम हो जाएगी। यह परीक्षण देश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रूज मिसाइल की त्रिशक्ति (ट्राइऐड) पूरी हुई है।

### देश भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया



#### **Tweet**



I compliment all those individuals and organisations working towards building more toilets in various parts of India. Their invaluable contribution adds solid momentum to Swachh Bharat Mission.

Narendra Modi @narendramodi

19 नवंबर को पूरे देश में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के एक हिस्से के रूप में राज्यों और जिलों में व्यवहार परिवर्तन और शौचालय के इस्तेमाल से जुडी जानकारियों और गतिविधियों के बारे में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किये गए। शौचालय की उपयोगिता और इसके इस्तेमाल के बारे में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त भारत के लिए लोगों की सिक्रय भागीदारी बढ़ाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

#### स्वच्छ भारत की दिशा में प्रगति



ओडीएफ गाँवों की संख्या- 2,76, 393



ओडीएफ शहरों की संख्या- 1,337



निर्मित शौचालयों की संख्या-

5, 85, 04, 277

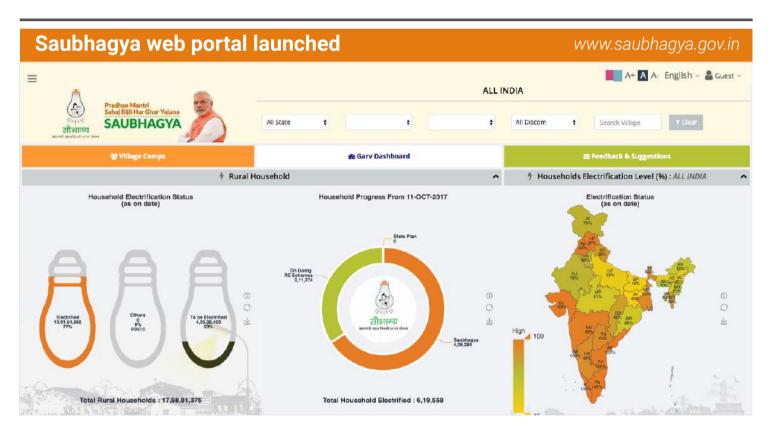






In an effort to boost the logistics sector in the country, the Government has granted infrastructure status to the logistics sector. As per the notification issued, the infrastructure sub-sectors category has been widened to "transport and logistics". The category includes industrial parks, warehouses, cold storages and transportation.

The infrastructure status for logistics will stimulate both domestic and external demand thereby encouraging manufacturing and job creation. India's high logistics costs are a major impediment to its global competitiveness and therefore the decision is significant in reducing them.



Prime Minister Narendra Modi launched the Saubhagya scheme on September 25, 2017. The scheme aims to provide last mile electricity connectivity to all rural and urban households. Recently a web portal was launched to help citizens to get all information on the current status of the work on electrification of various areas.

The portal also offers a feature on village electrification camps that will be organized by DISCOMs in villages. The portal will also be used for announcements and information dissemination on household electrification status (state, district, village-wise), and household progress on live basis.

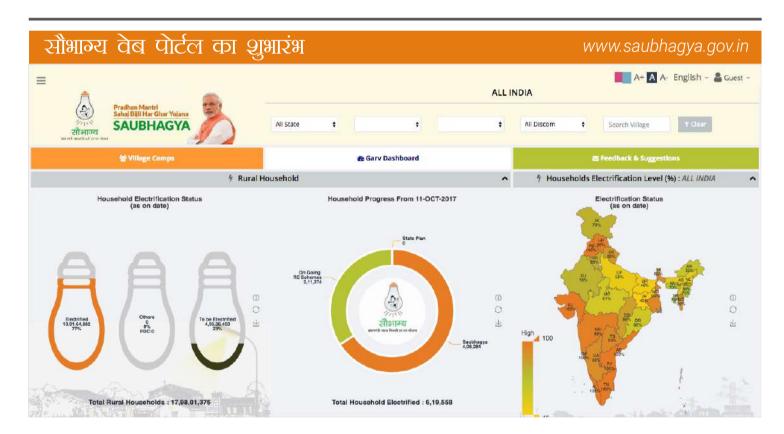








देश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। अधिसूचना के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर की उप-श्रेणी में बदलाव कर इसे "परिवहन और लॉजिस्टिक्स" किया गया है। इस श्रेणी में औद्योगिक पार्क, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन शामिल हैं। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से घरेलू और बाहरी दोनो ही मांग बढ़ जाएगी जिससे विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक्स लागत ज्यादा होने से घरेलू एवं निर्यात दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता घट जाती है और उन्हें कम करने में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लक्ष्य सभी ग्रामीण और शहरी घरों को बिजली प्रदान करना है। हाल ही में नागरिकों को बिजलीकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी देने हेतु 'सौभाग्य' वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।

सौभाग्य वेब पोर्टल में ग्रामीण बिजलीकरण शिविरों के बारे में एक फीचर है और इस फीचर के अनुरूप बिजली वितरण कंपनियां गांवों/गांवों के समूहों में शिविर लगाएंगी। पोर्टल के जिरए घरेलू बिजलीकरण की स्थिति (राज्य, जिला, गांवों के क्रम में), लाइव आधार पर प्रगति, और उपलिख की जानकारी मिलेगी।





#### India becomes second largest fish producing country in the world

The total fish production for India reached 11.41 million tonnes in 2016-17 making the country the second largest fish producing country in the world. Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh announced this milestone at a conference of World Fisheries Day.

Due to 'Blue Revolution' which was launched with an outlay of Rs. 300 crore for the holistic development of the Fisheries sector, overall fish production has recorded an increase of about 18.86% in comparison to the last three years. Inland fish production has also registered a growth of more than 26%.

At the event, the government also took significant decisions to safeguard the interests of traditional fishermen in the area of Exclusive Economic Zone (EEZ) beyond 12 nautical miles.

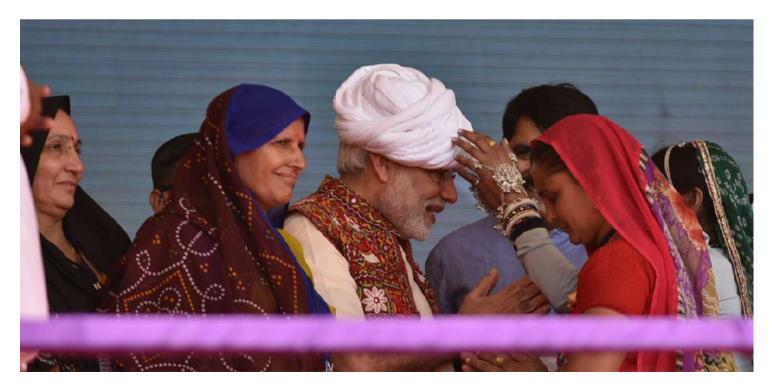


This includes the use of LED lights for fishing and a ban on the practice of bull-trailing.

# Towards empowerment: Mahila Shakti Kendras to be launched

The Narendra Modi Government has always strived towards a secure and conducive environment for the growth and empowerment of women in all spheres. The Central Government took another step towards this mission with the approval of setting up 'Mahila Shakti Kendras' across 115 most backward districts of the country. The centers will reach out to women and facilitate skill development, employment and will also focus on digital literacy, health and nutrition.

To make this a seamless process, more than 3 lakh student volunteers from local colleges will be a part of the process. NSS and NCC cadre students will also participate in the functioning of these centers. Further, the Government has also approved the expansion of Beti Bachao Beti Padhao scheme from 161 districts to 640 districts.





### दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना भारत

2016-17 में देश में कुल मछली उत्पादन 11.41 मिलियन टन तक पहुँच गया है। इसके साथ ही भारत, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने विश्व मात्स्यिकी दिवस समारोह में यह घोषणा की।

देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भारत सरकार ने 300 करोड़ की लागत से 'नीली क्रांति' की शुरूआत की। इसके परिणामस्वरुप समग्र मछली उत्पादन में गत तीन वर्षों में तुलनात्मक रूप में लगभग 18.86% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबिक अंतः स्थलीय मात्स्यिकी क्षेत्र में 26% वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवसर पर सरकार ने 12 समुद्री मील से परे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के क्षेत्र में पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी बताया।

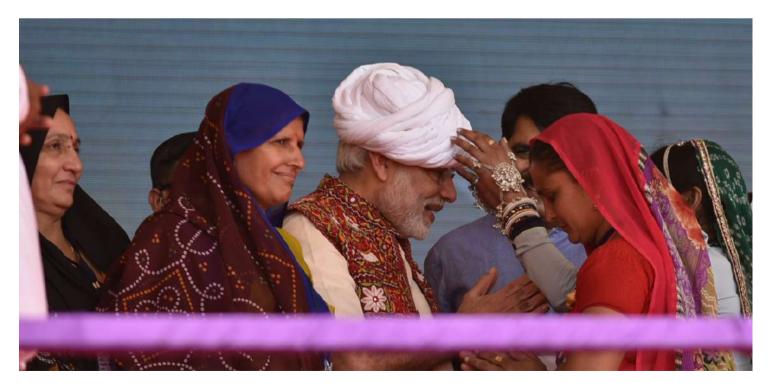


इन निर्णयों में मछली पकड़ने के लिए एलईडी लाइट और बुल ट्रालिंग के उपयोग पर पाबंदी प्रमुख है।

## सशक्तिकरण की दिशा में कदम: महिला शक्ति केंद्रों की होगी शुरूआत

सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा से एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल तैयार करने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में 'महिला शक्ति केंद्रों' की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों के जरिए महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह केंद्र रोजगार की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

इसे सुचारु रूप से लागू करने के लिए स्थानीय कॉलेजों के 3 लाख से अधिक छात्र स्वयंसेवकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एनएसएस और एनसीसी के छात्रों को भी इस काम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना को 161 जिलों से बढाकर 640 जिलों तक करने की मंजुरी दे दी है।







44

The global community needs to approach the issue of cyber-security with confidence, as much as with resolve. Cyberspace technologies must remain an enabler for our people.

Prime Minister Narendra Modi at GCCS 2017

77











